आम चुनावों में काले धन पर रोक लगाने के लिए उपाय

1304. **श्री प्यारेलाल खण्डेलवाल :**

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल :

श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आगामी आम चुनावों में काले धन के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए आवश्यक उपाय करने का इरादा रखती है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) किसी भी प्रयोजन के लिए, जिसके अन्तर्गत निर्वाचन भी हैं, काले धन के उपयोग पर केवल तभी रोक लगाई जा सकती है जब कि उसकी उत्पत्ति और वृद्धि पर रोक लगाने के उद्देश्य से उपाय किए जाएं । काला धन संबंधी विषय काफी जटिल है और यह संभव नहीं है कि केवल निर्वाचनों में उसके उपयोग पर रोक लगाए जाने के लिए पृथकतः कोई उपाय किए जाएं । सरकार ने कर अपवंचन और काले धन की उत्पत्ति पर रोक लगाने के लिए पहले ही कुछ विधायी और प्रशासनिक उपाय किए हैं । आर्थिक अपराधों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के भाग रूप इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ आय-कर अधिनियम का संशोधन, कर-संग्रहण तंत्र को चुस्त बनाना, कर संबंधी जानकारी का समाकलन और प्रसार, तलाशियां और अभिग्रहणों आदि को तीव्र करना सम्मिलित है ।

मध्य प्रदेश में टेलीफोन उपस्करों की चोरी

1305. **श्री प्यारे लाल खण्डेलवाल.** क्या **संचार** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इन्दौर से प्रकाशित होने वाले 'दैनिक स्वदेश' में 28 अप्रैल, 1984 को छपे इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि मार्च-अप्रैल, 1984 में जबारा (मध्य प्रदेश) में टेलीफोन उपस्करों की चोरी की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में उनके विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां ।

(ख) यह सच है कि वर्ष 1983 के दौरान जावड़ा में दूरसंचार लाईन सामग्री की चोरी हुई थी । पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है ।

Slow Rehabilitation of Released Bonded Labour

1306. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that as per the Report of Planning Commission only 41.2 per cent of released bonded labour were rehabilitated;

(b) if so, whether there has been failure in certain States due to late release of funds by the Central Government; and

(c) whether Government propose to set up a full time commission for labour, specially for child labour, bonded labour, daily paid staff and handicapped labour?